

वीरातालिंगम और अन्य

बनाम

रामेश और अन्य

18 सितंबर 1990

[न्यायाधिपति ललित मोहन शर्मा और न्यायाधिपति के. रामास्वामी]

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925: धारा 174-वसीयत-दस्तावेज की भाषा से अलग माने जाने वाले कारकों की व्याख्या-पूर्ववर्ती अनुवर्तीता का सहारा।

संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882: धारा 14-शाश्वतता के खिलाफ नियम याचिका की अस्वीकृति-जब उत्पन्न होती है।

मुकदमे में संपत्ति वादी और प्रतिवादी संख्या 5 से 14 की परदादी की थी जिन्होंने एक पंजीकृत वसीयत निष्पादित की थी। वसीयत की शर्तों के अनुसार, उसके दो बेटों, प्रतिवादी नंबर 1 और वादी के गवाह नंबर 2 को करों का भुगतान करने के लिए अलगाव की किसी भी शक्ति के बिना संपत्तियों पर कब्जा रखना था और वयस्क होने पर नियमित रूप से कुछ धार्मिक त्योहारों और उनके पुरुष मुद्दों का आयोजन करना था। संपत्ति को बराबर भागों में प्राप्त करना था और उसका पूरा आनंद लेना था।

मुकदमे में मुख्य विवाद उस हिस्सेदारी के बारे में था जिसके लिए वादी उपरोक्त वसीयत की शर्तों के तहत हकदार हैं। वादी ने दावा किया कि

वे वसीयतकर्ता के छोटे बेटे के एकमात्र पोते होने के नाते वसीयतकर्ता में आधे हिस्से के हकदार थे। शेष संपत्ति का आधा हिस्सा प्रतिवादी नंबर 1 के पोते-पोतियों को दिया जाएगा, अर्थात् प्रतिवादी नंबर 5 से 14 तक। यह मुकदमा प्रतिवादियों की ओर से लड़ा गया था, जिन्होंने दलील दी थी कि मुकदमे की संपत्तियों को सभी 13 पोते-पोतियों के बीच विभाजित किया जाना चाहिए। समान शेयरों में वसीयतनामा, और मुकदमा प्रतिवादी संख्या के रूप में खारिज करने के लिए उपयुक्त था। प्रतिवादी संख्या 1 ने अंततः 1975 में संपत्तियों का विभाजन कर दिया था, और आगे विभाजन का कोई सवाल ही नहीं उठता। मुकदमे की रखरखाव को भी चुनौती दी गई थी। वादी की अल्पसंख्यकता के आधार पर तथा शाश्वतता के विरुद्ध नियम के आधार पर भी।

विचारण न्यायालय ने शाश्वतता के विरुद्ध नियम के आधार पर याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1, उसके भाई और प्रतिवादी संख्या 15 के हित को ध्यान में रखते हुए, यह अभिनिर्धारित किया कि 1975 का कथित विभाजन अवैध था और वादी पर बाध्यकारी नहीं था और जहां तक वादी और प्रतिवादी संख्या 15 के शेयरों का संबंध है। 5 से 14 संबंधितों का मानना है कि पक्ष प्रति व्यक्ति के रूप में संपत्तियों को लेंगे। हालाँकि मुकदमे को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि वादी अभी भी नाबालिग थे।

वादियों द्वारा उच्च न्यायालय में की गई अपील में, उच्च न्यायालय ने विचारण अदालत के निष्कर्षों की पुष्टि की कि 1975 का विभाजन अवैध था, लेकिन यह अभिनिर्धारित किया कि विभाजन आंदोलनों के अनुसार होगा, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपील के लंबित रहने के दौरान, दो वादी वयस्क हो गए थे, उच्च न्यायालय ने प्रत्येक के एक-छठे हिस्से के लिए उनके पक्ष में एक डिक्री पारित की। जहाँ तक तीसरे वादी का संबंध है, उसने विभाजन के लिए डिक्री पारित किए बिना अपने अधिकार की घोषणा की।

अपीलकर्ताओं-प्रतिवादियों ने उच्च न्यायालय के फैसले को विशेष अनुमति द्वारा इस न्यायालय में चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि वसीयत की शर्तों के अनुसार वसीयतकर्ता के परपोते को प्रति व्यक्ति के अनुसार सूट की संपत्ति विरासत में मिली है और उच्च न्यायालय का निष्कर्ष इस पहलू पर अवैध था, और बोड्डू-वेंकटकृष्ण राव और अन्य बनाम श्रीमती बोड्डू सत्यवती और अन्य [1968] 2 एससीआर 395 पर उच्च न्यायालय द्वारा निर्भरता इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं थी।

आंशिक रूप से अपील की अनुमति देते हुए, और सभी वादी पक्ष के पक्ष में मुकदमे का फैसला सुनाते हुए, कि इस न्यायालय में मुकदमे की संपत्तियों में तीन वादी और प्रतिवादी संख्या 5 से 14 तक का हिस्सा प्रत्येक का एक-तेरह होगा,

अभिनिर्धारित किया गया :

1. एक अदालत को वसीयत का अर्थ लगाते समय यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि वसीयतकर्ता का इरादा मुख्य रूप से दस्तावेज़ की भाषा से एकत्र किया जाना है; लेकिन ऐसा करते समय आसपास की परिस्थितियों में वसीयतकर्ता की स्थिति, उसके पारिवारिक संबंध और इस संभावना को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उसने एक विशेष अर्थ में शब्दों का उपयोग किया है। वे वसीयत के सही निर्माण तक पहुँचने में एक मूल्यवान सहायता प्रदान करते हैं। चूँकि ये विचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बदल रहे हैं, इसलिए एक वसीयत के शब्दों की तुलना दूसरे वसीयत के शब्दों से करना या यह पता लगाने की कोशिश करना शायद ही कभी लाभदायक होता है कि जिन वसीयतों पर रिपोर्ट किए गए मामलों में निर्णय दिए गए हैं, उनमें से विवादित वसीयत निकटता से अनुमानित होगी। इसलिए, उदाहरणों का सहारा केवल निर्माण के सामान्य सिद्धांतों के उद्देश्य तक ही सीमित होना चाहिए।

2. अभी भी एक और कारण है कि निर्माण निश्चित क्यों किया गया है वसीयत में अभिव्यक्तियों को विचाराधीन वसीयत में समान अभिव्यक्ति पर लागू नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वसीयत को समग्र रूप से माना और समझा जाना चाहिए, न कि टुकड़े-टुकड़े में। यह इस प्रकार है कि एक ही अभिव्यक्ति का एक निष्पक्ष और उचित निर्माण इच्छा से इच्छा में भिन्न हो सकता है।

3. इसलिए, वसीयत के निर्माण के मामले में, अधिकारियों या उदाहरणों से कोई मदद नहीं मिलती है क्योंकि प्रत्येक वसीयत को अपने स्वयं के संदर्भ में और उस सेटिंग में समझा जाना चाहिए जिसमें खंड होते हैं।

वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने वसीयत के महत्वपूर्ण हिस्से की व्याख्या की है जिसमें 'समभागमगा अदिंथु' अभिव्यक्ति शामिल है, जिसमें एक तरफ वादी को और दूसरी तरफ 14 प्रतिवादियों को "प्रत्येक शाखा से समान रूप से साझा करने" का निर्देश दिया गया है। उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा दृष्टिकोण अपनाने का मुख्य कारण यह है कि वसीयत की शर्तें जो बोड्डू वेंकटकृष्ण राव और अन्य बनाम श्रीमती बोड्डू सत्यवती और अन्य [1968 [2 एससीआर 395;] मामले में व्याख्या का विषय थी; कमोबेश एक जैसे थे. यह भी माना गया है कि संपत्तियाँ अंततः दो शाखाओं में समान शेयरों में आ गईं और परिणामस्वरूप दोनों शाखाओं से संबंधित पक्षों को संपत्तियों को धारियों के अनुसार विरासत में मिला। ऐसा करते समय न्यायालय इस बात पर ध्यान देने में विफल रहा कि उस मामले के प्रासंगिक तथ्य और परिस्थितियाँ व्यापक रूप से भिन्न थीं। वर्तमान मामले से भिन्न। इसलिए वसीयत के निर्माण पर उच्च न्यायालय का निष्कर्ष सही नहीं था।

तत्काल मामले में, संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है, और किसी भी पक्ष द्वारा इस बात से इनकार नहीं किया गया है कि न तो वसीयतकर्ता के

बेटों और न ही पोते-पोतियों को संपत्तियों में कोई जीवन संपत्ति मिली है, यह पार्टियों का सहमत मामला है कि जितनी जल्दी हो सके जैसे ही वादी और प्रतिवादी क्रमांक 5 से 14 बालिग हो जाते हैं, वे अपने पिता या दादा की मृत्यु की प्रतीक्षा किए बिना संपत्ति प्राप्त करने के हकदार हो जाते हैं। इसलिए रिपोर्ट किए गए मामले में वसीयत को दिए गए अर्थ से प्रभावित हुए बिना वसीयत की व्याख्या की जानी चाहिए।

4. वसीयत के तहत संपत्ति का हस्तांतरण होता है वादी और प्रतिवादी संख्या 5 से 14 पहली बार 'समान शेयरों के तहत चूंकि यह संपत्ति में शेयरों को परिभाषित करने का पहला अवसर है, अभिव्यक्ति बराबर शेयरों' को वसीयतकर्ता के द्वारा छोड़ी गई संपूर्ण संपत्तियों को संदर्भित करना होगा जिन्हें विभाजित करना होगा वसीयतकर्ता के द्वारा सभी तरह परपोतों के बीच समान रूप से। दूसरे शब्दों में, वे संपत्ति को प्रति व्यक्ति के हिसाब से लेते हैं, तीसरे वादी ने भी अपील के लंबित रहने के दौरान वयस्कता हासिल कर ली है और इसलिए वह संपत्तियों में हिस्सेदारी का हकदार बन गया है। मुकदमे का फैसला सभी पक्षकारों के पक्ष में सुनाया जाता है, उनका हिस्सा प्रत्येक का तेरहवां हिस्सा होता है

रामचंद्र शेनॉय और अन्य बनाम श्रीमती हिल्डा ब्रिट और अन्य,
[1964]2 एस. सी. आर. 722 पर भरोसा किया।

बोड्डू वेंकटकृष्ण राव और अन्य बनाम श्रीमती बोड्डू सत्यवती और
अन्य[1968] 2 एससीआर 395, विशिष्ट।

5. यह दलील कि वसीयत के तहत स्वभाव शाश्वतता के खिलाफ
नियम से प्रभावित था, ट्रायल कोर्ट ने इस आधार पर सही खारिज कर
दिया था कि वसीयतकर्ता के बेटे और उनके संबंधित बेटे भी जीवित थे।

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 2231/1988

1982 की अपील संख्या 86 में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय
और आदेश दिनांक 19.8.1987 से।

आर वेंकटरमानी अपीलार्थी के लिए

उत्तरदाताओं के लिए एस. बालाकृष्णन और एम. के. डी. नम्बूदिरी।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

न्यायाधिपति शर्मा :

1. विशेष अनुमति द्वारा यह अपील विभाजन के एक मुकदमे में
वादी-प्रतिवादियों के पक्ष में उच्च न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के विरुद्ध
निर्देशित है।

2. मुकदमे में संपत्ति श्रीमती रथिनम्मल की थी, जिनकी एक
पंजीकृत वसीयत निष्पादित करने के बाद 1942 में मृत्यु हो गई। वसीयत

की शर्तों के अनुसार, उनके दो बेटे नटेशन, प्रतिवादी नंबर 1, और सुब्रमण्यम वादी के गवाह नंबर 2 (पीडब्लू -2), थे। बिना किसी अलगाव की शक्ति के संपत्तियों पर कब्जा बनाए रखना होगा और करों का भुगतान करना होगा और नियमित रूप से कुछ धार्मिक त्योहारों का आयोजन करना होगा; और उसके बाद उनके बेटों को समान शर्तों पर संपत्तियों का प्रबंधन करना था। वसीयत में आगे प्रावधान है कि उनके वयस्क होने के बाद परपोते, यानी वसीयतकर्ता के बेटे के बेटों को संपत्ति पूर्ण मालिक के रूप में मिलेगी।

3. वसीयतकर्ता का छोटा बेटा सुब्रमण्यम, जिसकी वर्तमान मुकदमे में वादी की ओर से दूसरे गवाह के रूप में जांच की गई है, का एक बेटा अरुणाचलम, प्रतिवादी नंबर 15 है। तीन वादी, रमेश, गणेश और शिवलिंगम, प्रतिवादी संख्या 15 के पुत्र हैं। प्रतिवादी संख्या 1 के चार पुत्र और दस पुत्र के पुत्र हैं। मुकदमे में मुख्य विवाद उस हिस्से को लेकर है जिसके वसीयत की शर्तों के तहत वादी हकदार हैं। उनका दावा है कि सुब्रमण्यम के एकमात्र पोते होने के नाते उनका संपत्ति में आधा हिस्सा है, शेष आधा हिस्सा प्रतिवादी नंबर 1 के पोते-पोतियों को जाता है, यानी प्रतिवादी नंबर 5 से 14 तक। प्रतिवादियों की ओर से यह दलील दी गई है कि मुकदमे की संपत्तियों को वसीयतकर्ता के सभी 13 पोते-पोतियों के बीच समान शेयरों में विभाजित किया जाना है। प्रतिवादियों ने यह भी तर्क दिया कि मुकदमा खारिज किए जाने योग्य था क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 और

प्रतिवादी संख्या 15 ने अंततः 1975 में संपत्तियों का विभाजन कर दिया था और आगे के विभाजन का कोई सवाल ही नहीं उठता। मुकदमे की स्थिरता को अल्पसंख्यक के आधार पर भी चुनौती दी गई थी। वादी और शाश्वतता के विरुद्ध नियम के आधार पर भी।

4. विचारण न्यायालय ने शाश्वतता के खिलाफ नियम के आधार पर याचिका खारिज कर दी। प्रतिवादी नंबर 1, उसके भाई सुब्रमण्यम और अरुणाचलम, प्रतिवादी नंबर 15 के हितों को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने माना कि 1975 का कथित विभाजन अवैध था और वादी पर बाध्यकारी नहीं था। जहां तक वादी और प्रतिवादी संख्या 5 से 14 के शेयरों का सवाल है, बचाव पक्ष के मामले से सहमत होते हुए, अदालत ने माना कि पक्षकार व्यक्ति के अनुसार संपत्ति लेंगे। हालाँकि मुकदमा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि वादी अभी भी नाबालिग थे

5. वादी पक्ष की अपील पर, उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के इस निष्कर्ष की पुष्टि की कि 1975 का विभाजन अवैध था। पार्टियों के शेयरों के सवाल पर, उच्च न्यायालय ने वादी के साथ सहमति व्यक्त की और माना कि विभाजन हलचल के अनुसार होगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपील के लंबित रहने के दौरान दो वादी बहुमत प्राप्त कर चुके थे, उच्च न्यायालय ने उनके पक्ष में प्रत्येक को छठा हिस्सा देने का डिक्री पारित कर दिया। जहां तक तीसरे वादी का सवाल है, उच्च न्यायालय ने विभाजन की डिक्री पारित किए बिना ही उसके अधिकार की घोषणा कर

दी। प्रतिवादी वर्तमान सिविल अपील द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती दे रहे हैं।

6. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि वसीयत की शर्तों के अनुसार वसीयतकर्ता के परपोते को प्रति व्यक्ति के अनुसार मुकदमे की संपत्ति विरासत में मिली है और इस पहलू पर उच्च न्यायालय का निष्कर्ष अवैध है। वसीयत के ऑपरेटिव हिस्से का अंग्रेजी संस्करण ट्रायल कोर्ट के फैसले के पैराग्राफ 7 में उद्धृत किया गया है और हमारे सामने किसी भी पक्ष ने इसे चुनौती नहीं दी है। अपने बेटों के अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लेख करने के बाद टेस्टाट्रिक्स ने अपने पोते-पोतियों और परपोतों की स्थिति इस प्रकार बताई है:

"उन्हें (अर्थात् पुत्रों के पुत्रों को) भी कर चुकाना पड़ता है और अपनी आय से नियमित रूप से उपरोक्त त्योहारों का आयोजन करना पड़ता है। फिर उनके पुरुष पुत्रों को वयस्क होने के बाद, समान शेयरों में उक्त संपत्तियों पर कब्जा करना होता है और उनका आनंद लेना होता है। अलगाव की सभी शक्तियों के साथ।"

हमारे समक्ष पक्षकारों के विद्वान वकील द्वारा यह कहा गया है कि शब्द "उक्त संपत्ति समान शेयरों में" समभागमग अदंथु शब्द का अंग्रेजी संस्करण है।

अपीलकर्ताओं के वकील ने वसीयत के इस हिस्से का अनुवाद करते हुए कहा कि,

"वे (अर्थात्, बेटों के बेटे) सरकार को देय करों का भुगतान करेंगे और बिना किसी असफलता के धर्मार्थ/धार्मिक गतिविधियों को जारी रखेंगे और उनके पुरुष पुत्रों को वयस्क होने पर समान हिस्से में संपत्ति मिलेगी (समभागमग अदंथु) और उनके पास होगा अपनाएं और इसका पूरा आनंद लें।"

महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति समभागमगा अदंथु है जो पक्षकारों के विद्वान वकील के अनुसार इसका अर्थ समान भागों में है। सवाल यह है कि क्या वसीयत में इस प्रावधान के मद्देनजर वसीयतकर्ता द्वारा छोड़ी गई संपूर्ण संपत्तियों को उसके सभी पोते-पोतियों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए; या, तीनों वादी आपस में आधा-आधा ले लेंगे, शेष आधा अपने चचेरे भाइयों को दे देंगे।

7. उच्च न्यायालय ने पूर्ववर्ती पैराग्राफ में उल्लिखित वसीयत के महत्वपूर्ण भाग की व्याख्या इस प्रकार की है, जिसमें एक ओर वादी को और दूसरी ओर प्रतिवादी 5 से 14 को क्रमशः "प्रत्येक शाखा से समान रूप से साझा करने" का निर्देश दिया गया है। यह माना गया है कि संपत्तियाँ अंततः दो शाखाओं में समान शेयरों में विभाजित हो गईं। और परिणामस्वरूप दोनों शाखाओं से संबंधित पार्टियों को संपत्तियाँ स्टिरपेज के

रूप में विरासत में मिलीं। उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा दृष्टिकोण अपनाने का मुख्य कारण वसीयत की शर्तें हैं। जो बोड्डू वेंकटकृष्ण राव और अन्य बनाम श्रीमती बोड्डू सत्यवती और अन्य [1968] 2 एससीआर 395 के मामले में व्याख्या का विषय था; कमोबेश समान थे जिन्हें इस न्यायालय ने हमारे सामने मामले में वादी द्वारा सुझाए गए तरीके से समझा। हम उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं।

8. यह सर्वमान्य है कि वसीयत बनाते समय न्यायालय को प्रयास करना चाहिए मुख्य रूप से दस्तावेज़ की भाषा से इकट्ठा किए जाने वाले वसीयतकर्ता के इरादे का पता लगाना; लेकिन ऐसा करते समय आस-पास की परिस्थितियों, वसीयतकर्ता की स्थिति, उसके पारिवारिक संबंध और इस संभावना को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उसने शब्दों का इस्तेमाल एक विशेष अर्थ में किया है। वे वसीयत के अंतिम निर्माण तक पहुंचने में अमूल्य सहायता प्रदान करते हैं। चूंकि ये विचार व्यक्ति दर व्यक्ति बदल रहे हैं, इसलिए एक वसीयत के शब्दों की तुलना दूसरे वसीयत के शब्दों से करना या यह पता लगाने की कोशिश करना शायद ही लाभदायक है कि रिपोर्ट किए गए मामलों में किस वसीयत पर निर्णय दिए गए हैं, विवादित वसीयत बारीकी से अनुमानित है। इसलिए, मिसालों का सहारा केवल निर्माण के सामान्य सिद्धांत तक ही सीमित रखा जाना चाहिए, जो अब तक अच्छी तरह से स्थापित हो चुके हैं। अभी भी एक और कारण है कि

वसीयत में कुछ अभिव्यक्तियों पर किए गए निर्माण को वसीयत में प्रश्न के तहत समान अभिव्यक्ति पर लागू नहीं किया जाना चाहिए।

समग्र रूप से विचार और व्याख्या की जानी चाहिए, न कि टुकड़ों में। इससे पता चलता है कि एक ही अभिव्यक्ति का निष्पक्ष और उचित निर्माण इच्छा से इच्छा तक भिन्न हो सकता है। इन कारणों से यह बार-बार माना गया है कि निर्माण के मामले में वसीयत प्राधिकारियों या उदाहरणों से कोई मदद नहीं मिलती है क्योंकि प्रत्येक वसीयत को अपने स्वयं के संदर्भ में और उस सेटिंग में समझा जाना चाहिए जिसमें खंड होते हैं (रामचंद्र शेनॉय और अन्य बनाम श्रीमती हिल्डा ब्राइट और अन्य, [1964] 2 एससीआर 722 देखें पृष्ठ 736. इस संपूर्ण नियम की सराहना न करने का जोखिम हमारे सामने आए मामले से प्रदर्शित होता है।

9. यह मानते हुए कि बोड्जू वेंकटकृष्णराव और अन्य बनाम श्रीमती बोड्जू सत्यवती और अन्य [1968] 2 एससीआर 395; के मामले में वसीयत कुछ हद तक वर्तमान मामले में रिपोर्ट में वसीयत पर दिए गए निर्माण के बाद उच्च न्यायालय के समान थी। मामले में, अपील के तहत फैसले में कहा गया है कि वसीयतकर्ता के पोते-पोतियों को हलचल के अनुसार संपत्तियां लेनी होंगी। ऐसा करते समय न्यायालय यह ध्यान देने में विफल रहा कि उस मामले के प्रासंगिक तथ्य और परिस्थितियाँ वर्तमान मामले से बिल्कुल अलग थीं। वहाँ वसीयतकर्ता, जो एक निःसंतान विधवा थी, ने वसीयत के तहत जीवन सम्पदा दो बच्चों को दे दी थी, जो मामले

में प्रतिवादी 4 और 5 थे और जिन्हें उसने बचपन से ही पाला था, और उसी के अधीन संपत्ति उनके बच्चों को मिलनी थी। उनकी मृत्यु के बाद, वसीयत के निर्माण पर हाईकोर्ट की सहमति, जिससे यह न्यायालय सहमत था, इस प्रकार व्यक्त किया गया,

"प्रतिवादी 4 और 5 के पक्ष में वसीयत एक जीवन संपत्ति की थी जिसमें उनके बच्चों के पक्ष में निहित शेष था और बच्चों को प्रति व्यक्ति नहीं बल्कि प्रति व्यक्ति निहित शेष लेना चाहिए।"

हमारे सामने आए मामले में किसी के पक्ष में कोई जीवन संपत्ति सृजित नहीं की गई अन्यथा वादी पक्ष को अपने पिता और चाचा के जीवनकाल के दौरान वयस्क होने पर भी संपत्ति में कोई हिस्सा मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उच्च न्यायालय ने भी आक्षेपित निर्णय दिया है। देखा गया कि एक हिंदू से आम तौर पर संयुक्त किरायेदारी बनाने की उम्मीद नहीं की जाती है। यह समझने में असफल रहे कि केवल एक अनुमान है। इस आशय से, जो वसीयत के प्रावधानों को खत्म नहीं कर सकता, अगर भाषा स्पष्ट और स्पष्ट हो। वर्तमान मामले में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। और किसी भी पक्ष द्वारा इस बात से इनकार नहीं किया गया है कि न तो वसीयतकर्ता के बेटों और न ही पोते-पोतियों को संपत्तियों में कोई जीवन संपत्ति मिली। यह दोनों पक्षों की सहमति का मामला है कि जैसे ही वादी और प्रतिवादी संख्या 5 से 14 बालिग हो जाते हैं, वे अपने-

अपने पिता या दादा-दादी की मृत्यु की प्रतीक्षा किए बिना पूरी तरह से संपत्ति प्राप्त करने के हकदार हैं। इसलिए, हमें रिपोर्ट किए गए मामले में वसीयत को दिए गए अर्थ से प्रभावित हुए बिना वसीयत की व्याख्या करनी चाहिए।

10. वसीयत के तहत संपत्ति का हस्तांतरण वादी और प्रतिवादी क्रमांक 5 से 14 को पहली बार "समान शेयरों के तहत" होता है। चूंकि यह संपत्ति में शेयरों के लिए परिभाषित अभिव्यक्ति का पहला अवसर है "समान शेयर" का तात्पर्य वसीयतकर्ता द्वारा छोड़ी गई संपूर्ण संपत्तियों से है, जिसे वसीयतकर्ता द्वारा सभी तरह परपोते-पोतियों के बीच समान रूप से विभाजित करना होगा। दूसरे शब्दों में, वे व्यक्ति के अनुसार संपत्ति लेते हैं।

11. माना जाता है कि वर्तमान अपील के लंबित रहने के दौरान तीसरा वादी भी वयस्क हो गया है और इसलिए अब संपत्तियों में हिस्सेदारी का हकदार बन गया है। तदनुसार, मुकदमे का फैसला सभी वादी के पक्ष में सुनाया जाता है, उनका हिस्सा प्रत्येक का तरहवां हिस्सा होता है।

12. दलील यह है कि वसीयत के तहत स्वभाव नियम से प्रभावित हुआ था विचारण न्यायालय ने अपने फैसले के पैराग्राफ 7 में शाश्वतता के खिलाफ इस आधार पर खारिज कर दिया था कि वसीयतकर्ता के बेटे अर्थात् पहला प्रतिवादी और वादी का गवाह नंबर 2 और उनके संबंधित बेटे, प्रतिवादी नंबर 2 से 4 भी जीवित हैं। उच्च न्यायालय में इस मुद्दे पर जोर नहीं दिया गया, विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण सही प्रतीत होता है

और इस स्तर पर पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है। परिणामस्वरूप, ऊपर बताए अनुसार अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। तदुसार मुकदमे का फैसला तीनों वादी के पक्ष में सुनाया जाता है। मुकदमे की संपत्तियों में तीन वादी और दस प्रतिवादियों यानी प्रतिवादी संख्या 5 से 14 तक का हिस्सा प्रत्येक का तेरहवां होगा। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

एन वी के

अपील पक्ष की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता निशा पालीवाल द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।